‘शहर की खेती’

भारत के शहरों में खेती पर एक राष्ट्रीय जन सम्मेलन

11-12 अप्रैल, 2020

स्थान : **IRD** कांफ्रेंस सभागार, आईआईटी दिल्ली**,** हौज़ ख़ास, दिल्ली-16**.**

भागीदारी के लिए आमन्त्रण

जन संसाधन केंद्र और इंस्टिट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड सस्टेनेबिलिटी संयुक्त रूप से दो-दिवसीय सम्मेलन का आयोजन **11-12 अप्रैल 2020** को **दिल्ली** में कर रहे हैं. इस कार्यक्रम के निम्नलिखित उद्देश्य हैं:

- व्यवस्थागत मुद्दों जैसे खाद्य सुरक्षा, जन स्वास्थ्य, खराब होता पर्यावरण, ऊर्जा सुरक्षा, सामाजिक समरसता, भूमि उपयोग और उत्पादन के इर्द-गिर्द के सम्बन्ध, इत्यादि के सापेक्ष शहरी खेती की भूमिका पर एक जमीनी चर्चा की शुरुआत करना
- शहरी खेती करने वालों को संगठनकर्ताओं, शोधकर्ताओं और शहर में रूचि रखने वाले नागरिकों से जोड़ना, ताकि शहरी खेती का ज्ञानपरक पक्ष उभर सके और ज्ञान को साझा करने का तरीका निकाला जा सके
- राज्य और शहर से लेकर मोहल्ले के स्तर तक शहरी खेती समुदाय के सामूहिक संगठन (नेटवर्क, फोरम, प्लेटफार्म आदि) बनाने और मौजूद समूहों को मजबूत करने की संभावना तलाशना

हम शहर में खेती करने वालों, स्वास्थ्य, भोजन सुरक्षा, ऊर्जा, शहरी पर्यावरण, संसाधनों की राजनीति, शहरी विकल्पों आदि के क्षेत्र में कार्यरत शोधकर्ताओं और संस्थानों, नगर निकायों और उनसे सम्बद्ध व्यक्तियों/समूहों, और शहर में खेती के प्रति रूचि रखने वाले आम जनों को इस कार्यक्रम में भाग लेने, इसके संचालन में मदद करने, और इसे सार्थक बनाने के लिए आमंत्रित करते हैं.

प्रस्तावित गतिविधियाँ

- पैनल चर्चा/समूह चर्चा (चर्चा के लिए शोध पत्र/लेख)
- वक्तव्य, जानकारीपरक वर्कशॉप आदि
- दिल्ली में शहरी खेती की संक्षिप्त यात्रा और खेतिहर समुदाय से बातचीत

हम इच्छुक प्रतिभागियों से अनुरोध करते हैं कि चर्चाओं को सारगर्भित बनाने के लिए अपने शोध पत्र, लेख, समीक्षा, पोस्टर, डाक्यूमेंट्री फिल्म, पेंटिंग या फोटो प्रदर्शनी, नाटक या अन्य विधा की सांस्कृतिक प्रस्तुति, या अभिव्यक्ति के अपने पसंदीदा तरीके से निम्नलिखित में से किसी विषय के इर्द-गिर्द अपनी बात रखें:

चर्चा के विषय

A. **खेती को कैसे समझें:** खाद्य सुरक्षा, ऊर्जा सुरक्षा और कचरा प्रबंधन के अंतर्संबंधों के नजरिये से शहरी खेती की भूमिका को समझना और शहरी खेती को इन विचारों से जोड़ना- सामाजिक पारिस्थितिकी, आजीविका और सार्थक रोजगार, चक्रीय और साझा अर्थव्यवस्था का मॉडल, खेती की पारिस्थितिक बहुविधता, लिंग-आधारित और अन्य शक्ति संरचनाएं, विकेन्द्रीकृत व भागीदारीपरक शासन, आत्म-निर्भरता, शहर पर अधिकार और शहरों से जुड़े अन्य मुक्तिकामी विचार, कामकाजी वर्ग की एकता, आदि
B. **शहर के अभागे**: मौजूदा सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और कानूनी परिवेश में और जल, प्राकृतिक संसाधन और जमीन के इर्द-गिर्द चल रहे संघर्षों के परिपेक्ष्य में शहरी खेती की चुनौतियाँ
C. **शहरी खेती, ग्लोबल बाजार**: ग्लोबल और औद्योगीकृत खाद्य श्रृंखला के बजाय शहरी खाद्य तंत्र को अधिक से अधिक स्थानीय बनाने के पक्ष में दलीलें
D. **शहर और गाँव में खेती**: विरोधाभास की बजाय परस्पर पूरक संबन्ध, शहर की प्रभुता के बजाय पारस्परिकता, असुरक्षा की बजाय आत्म-निर्भरता
E. **मानसिक प्रभाव**: शहर में खेती करने के सांस्कृतिक, भावनात्मक और संवेदनात्मक पक्ष
F. **भावी शहरों में खेती**: तकनीकशाही से प्रेरित 'स्मार्ट सिटी' के विचारों और मानववादी 'आत्म-निर्भर' शहर के विचारों की तुलना
G. **खेतिहर शहर के लिए वचनबद्धता**: विविध अधिकारों को लेकर चल रहे शहरी और ग्रामीण जन-आन्दोलनों से संवाद, एकजुटता, संगठन
H. आपकी पसंद का कोई विषय जो शहर में खेती पर चर्चा में योगदान दे सकता हो और सामूहिक समझ बढ़ा सके

अभिव्यक्तियाँ भेजने के सम्बन्ध में निर्देश

- लिखित सामग्री और ऑडियो किसी भी भाषा में हो सकते हैं लेकिन प्रतिभागियों से अनुरोध है कि पूरी प्रस्तुति या उसके सारांश का हिंदी या अंग्रेजी भाषा में अनुवाद भी साथ में भेजें ताकि संवाद में भाषा की रूकावट न आये.
- शोध पत्र या लेख 10000 शब्दों से अधिक का न हो और उसका सारांश 500 शब्दों से अधिक न हो. कम समय में ज्यादा और विविध विचारों की प्रस्तुति हो सके इसलिए फिल्म/सांस्कृतिक प्रस्तुति की अधिकतम समय सीमा 90 मिनट है. आप प्रस्तुति की 10 मिनट से कम अवधि की छोटी ऑडियो/विडियो क्लिप सारांश के तौर पर पहले भेज दें.
- अपने लेखों/प्रस्तुतियों के सारांश हमें **15 जनवरी, 2020** तक जरुर भेज दें. सम्पूर्ण लेख/प्रस्तुति आप हमें **15 फरवरी, 2020** तक भेज सकते हैं.

पंजीकरण, आश्रय, यात्रा आदि के सम्बन्ध में किसी तरह के प्रश्न के लिए आप हमें idsinitiative@gmail.com पर ईमेल कर सकते हैं.

कार्यक्रम और वक्ताओं आदि के बारे में विस्तृत जानकारी जल्द ही प्रकाशित की जाएगी.

आयोजक

जन संसाधन केंद्र का लक्ष्य सामाजिक आन्दोलनों से प्राप्त मूल्यवान सीखों और संभावित विकल्पों को लेकर सब लोगों की कल्पनाओं को साथ लाकर एकजुटता का नया आधार बनाना है। यह पहल संसाधनों पर लोगों का नियंत्रण वापस लाने की संभावनाएँ बनाने के लिए, और यह समझने के लिए की गयी है कि कैसे इस जरिये भूख, बेघरी, प्रदूषण, और जाति, लिंग, धर्म पर टिके सामाजिक अन्याय का उन्मूलन कर सकते हैं। हम संसाधनों के हक़ के इर्द-गिर्द हो रहे (या संभावित) संघर्ष में आंदोलन समूहों और समुदायों के साथ जुड़कर योगदान करते हैं। सामूहिक प्रतिरोध और रचनात्मक कार्यक्रम के लिए संसाधन उत्पन्न करने के उद्देश्य से हम नियमित रूप से नीतियों की निगरानी, शोध, प्रकाशन और जमीनी स्तर पर नेटवर्किंग के उपाय करते हैं।

संपर्क: prc.india@yahoo.com

इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड सस्टेनेबिलिटी पिछले तीन दशकों से टिकाऊ शहरी परिवहन, समान सड़क अधिकार, आजीविका के अधिकार और शहर में खेती समेत सामाजिक परिवर्तन के कई मुद्दों पर सक्रिय रूप से काम करता रहा है। हमारे अनुसार पर्यावरण के अनुकूल, सामाजिक रूप से समावेशी, एक जिंदादिल शहर को विकसित करने की शर्त है कि रोजगार, आवास और शिक्षा के लिए गुणवत्ता और समता के मूल्यों पर आधारित अवसर उपलब्ध कराये जायें। हमारा मानना है कि इसके लिए स्थानीय और विकेन्द्रीकृत उत्पादन और वितरण प्रणाली को प्राथमिकता मिलनी चाहिए। हम जनांदोलनों के राष्ट्रीय समन्वय (NAPM), सस्टेनेबल अर्बन मोबिलिटी नेटवर्क ऑफ इंडिया (SUMNet), कार-फ्री नेटवर्क आदि के एक घटक सदस्य हैं और विविध राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों से जुड़े हुए हैं।

संपर्क: idsinitiative@gmail.com

तकनीकी सहयोग

ट्रांसपोर्टेशन रिसर्च एंड इंजुरी प्रिवेंशन प्रोग्राम (ट्रिप-TRIPP), आइआइटी दिल्ली सड़क यातायात के बुरे स्वास्थ्य प्रभावों को कम करने के उपायों पर शोध करने एक साझा कार्यक्रम है. ट्रिप के शोधकार्यों और आयोजनों का उद्देश्य यातायात से जुड़े सभी मुद्दों को एक साथ लाकर सुरक्षा, स्वच्छ पर्यावरण और ऊर्जा संचय को बढ़ावा देना है.